RAJYA SABHA

Wednesday, the 31 *st July,* 2002/9 *Sravana,* 1924 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up captive power plant for bower supply to Delhi in Korba-Chhattlsgarh

* 241. DR. AKHIKESH DAS: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether a captive coal based 1000 MW power plant for power supply to the capital is proposed to be set up in Korba-Chhattisgarh coal pit heads;

(b) if so, the details and cost thereof indicating the estimated distribution losses to be incurred thereby; and

(c) the economic justifications for the captive plant for Delhi being located at Korba-Chhattisgarh?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of National Capital Territory (NCT) of Delhi has proposed a 1000 MW coal based power plant in Korba-Chhattisgarh pit heads for supply of power to NCT of Delhi. The proporal is at a very preliminary stage. The Central Electricity Authority has been assigned the task of preparing of preliminary conceptual feasibility report for consideration of the project by the Government of NCT of Delhi.

(b) and (c) Since the proposal is still at the conceptual stage, it wolild be prerhature to Indicate details such as the cost, transmission and distribution losses; and economic justification.

डा. अखिलेश दास : उपसभापति महोदया, जो स्टेट्स का बंटवारा हुआ है, विशेष रूप से तीन प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश उसमें उन लोगों ने पॉवर को लेकर अपना जो आधार किया था, उसमें मैं उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अपनी जा पावर को लेकर संभावनाएं तलाशी गया थी, पांच साल के लिए नहीं बल्कि सौ वर्ष के लिए उसमें उत्तर प्रदेश का मुख्य आधार हिमालयन रीजन ही था। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए प्रयास यह किया गया कि थर्मल पावर के स्थान पर हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिक से अधिक प्रयास किया जाये। आज हालत यह है कि रिहंद के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई हाइडल प्रोजेक्ट ही नहीं है। सारे के सारे जितने भी हाइडल प्रोजैक्ट्स हैं, वे उत्तरांचल में ही केन्द्रित है और आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गयी है कि वह प्रदेश अधंकार मे डूबा हुआ है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी संभावना है कि केन्द्र सरकार और आपका मंत्रालय इस तरह का कोई प्रयास कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए , वहां पर उनकी आर्थिक तंगहाली को देखते हुए और जो पूरे संसाधन उत्तरांचल में चले गये हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या उत्तर प्रदेश को निःशुल्क बिजली या सस्ती दरों पर बिजली दी जाए? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई ऐसा कैप्टिव पॉवर प्लांट लगाने का विचार केन्द्र सरकार का है?

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, जो प्रश्न पूछा गया है, वह दिल्ली सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने मिलकर एक साझा प्रोजेक्ट बनाने की जो भावना सी.ई.ए. के पास व्यक्त की है, उसके बारे में हैं लेकिन आपने जो सवाल किया है, वह उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बटंवारे के बारे में है। लेकिन आपने जो सवाल किया है, वह उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बटंवारे के बारे में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल गवर्नमेंट में मिलकर जो फैसला किया था, उस पर केन्द्र सरकार ने अपनी मुहर लगाई थी। आज भी यदि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तरांचल में, क्योंकि हाइड्रों प्रोजैक्ट वही लगाया जा सकता है जहां पानी है और पानी उत्तरांचल के पास है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार यदि वहां कोई प्रोजैक्ट लगाना चाहेगी तो केन्द्र सरकार उसको पूरा समर्थन करेगी।

डा. अखिलेश दास : महोदया, जैसा कि इस प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि The proposal is at the conceptual stage, जो हाल आज बिजली का है, पूरा पश्चिमी पॉवर ग्रिड समाप्त हो गया है। रेल जहां की तहां, ज्यों की त्यों खड़ी है। पूरा प्रदेश ही अंधकारमय हो गया है। कब तक यह कन्सैप्चुअल स्टेज पर रहेगा। जहां तक मैं समझता हूं यह दिल्ली सरकार द्वारा काफी पुराना प्रपोजल दिया हुआ है, कितने दिनों तक यह प्रपोजल पैंडिग रहेगा। कब तक इस पर कॉन्सैप्ट बनेगा? कितने वर्ष इमसें लगेंगे? यह अपने आपमें आश्चर्य पैदा करता है क्योंकि जैसा आपने कहा कि अब तक यह नहीं आया है कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कास्ट से किस तरह का इसका आधार बनेगा। इसका मतलब अभी तक कोई विशेष कार्यवाही इस विषय में नहीं हुई है जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर बिजली नहीं है तो किसी प्रकार के विकास की संभावना

ही नहीं हो सकती। वहां पर इतने महत्वपूर्ण विषय अभी तक इस स्टेज पर हैं कि विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्पैसिफिकली कोई ऐसा टाइम आप निर्धारित करेंगे, जो कोरबा- छत्तीसगढ़ में दिल्ली सरकार ने प्रपोजल दिया है क्या इस संबंध में कोई टाइम बांउड कार्यक्रम है जब तक इस पर पूरी कार्यवाही चालू हो जाएगी?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो जो प्रोजैक्ट प्रपोनेंट है, इस मामले में दिल्ली सरकार यदि कोई प्रोजैक्ट बनान चाहती है तो उसके लिए सिर्फ टैक्नोइकनांमिक क्लीयरेंस के लिए ही केन्द्र सरकार के पास, सी.ई.ए के पास आना पड़ता है। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने कोई फर्म प्रपोजल नहीं बनाया है। सिर्फ प्रपोजल बनाने के लिए उन्होंने सी.ई.ए. को ऐडवाइजर अप्वायंट किया है। इसलिए कोई भी फर्म प्रपोजल केन्द्र सरकार के पास आज विचाराधीन नहीं है। आपने दिल्ली की स्थिति के बारे में कहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की यह स्थिति किस लिए हैं। दिल्ली की टोटल रिक्वायरमैंट ऑफ पावर 3300 मेगावाट है। दिल्ली की अपनी जेनरेशन 700 मेगावॉट भी नहीं है और दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है, वह 2700 मेगावॉट से भी ज्यादा है। इसलिए उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम दिल्ली के बाहर से बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास किया है जो आज ठक के प्रयासों में सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि अपनी तरफ से जेनरेशन बढ़ाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है और इसके लिए यदि दिल्ली सरकार चाहती है कि जल्दी प्रोजेक्ट बने तो उसका टेक्नो-इकानॉमिक क्लीयरेंस बना कर वह जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार के पास भेज दे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उसको फौरन अनुमति दे देंगे।

SHRI JANARDHANA POOJARY: Madam, there was an unprecedented breakdown of power supply in Northern India yesterday. The entire area was plunged into darkness. According to an estimate, the total requirement of the area is 20,000 MW. But the Government is in a position to supply only 3,000 MW of power.

Madam, you know that there is a drought situation in the entire country. Unfortunately, the cost of generation of power in the hydel sector is tower than the cost of generation in other sectors. The question is, if the drought situation persists, there will be shortage everywhere. Then, the Government will not be in a position to supply power. Under these circumstances, how are you going to tackle the situation? You are going to declare half country as drought-affected. In this regard, I would like to know whether you are going to reduce the price of power, per unit, that you supply to the States affected by drought. Otherwise, they would not be in a position to purchase power. For example, in Karnataka, there is a

reservoir called Linganamakki but there is no "water there. The Government of Karnataka is, practically, not in a position to supply power. Definitely, the Government of Karnataka is going to come before the Centra) Government with a proposal to supply more power from the National Grid Sir, I would like to know whether you would supply power at subsidised rates, so far as the drought-affected States are concerned?

SHRI SURESH PRABHU: Madam, it is a fact that this year, because of lower rainfall, we are estimated to lose somethingfike 12 billion units of extra generation, which, otherwise, would have been generated, using the hydel source. Therefore this is a very serious matter. This is the second year in succession in States like Karnataka. In the case of Karnataka, unfortunately, last year also, it faced a similar situation. This is the second year in row. The situation is really bad.

In the case of Kerala, the reservoir level is 46% of what it was last year. It is a very, very serious matter. Unfortunately, all over the country, the reservoir levels are low. Even in the Northern Grid, we are facing a 30% lesser generation, as a result of less availability of water. Therefore, we have prepared a contingency plan. I have called a meeting of Power Ministers of all the States, on 5th August, 2002. We have prepared a plan under which we are going to tackle this problem in six ways: One, we are trying to increase the thermal generation. To reduce the cost of thermal power generation, we are trying to find out how the liquid fuel-cost which will be used as a fuel can be reduced. We are already trying to find out if the excise duties can be reduced. Also, we are requestihg all the States to reduce the sales tax on naphtha so that the cost can be further reduced.

Secondly, we are postponing the annual repairs and maintenance of the existing thermal plants so that more power can be generated this year.Thirdly, the renovation and modernisation of our existing power plants, which otherwise would have been taken up in the next five years, has been taken up during this year so that, maybe, some of those power plants are available for power generation within this year itself.

Energy conservation and demand management is another area, which we are targeting. On 23rd August.our hon. Prime Minister would be inaugurating a conference where we will try to find out how the ehergy can be conserved and saved during this short period of time. Then, there are certain prdjects which are working at lower plant load factor like in the

case of Bihar where the plant load factor is about 20 per cent. We are trying to activate those projects and we are trying to evacuate that power from the Eastern Region to the rest of the country. Therefore, the transmission networking has been preponed.The commissioning schedule has been preponed.TheTalcher-Kolar line which is going to bring power to Karnataka irt a big way has been preponed by one-and-half years. It is a record. Therefore, we are trying to do several things, including finding out whether any independent power capacity is lying idle which can be used. It includes captive capacity also. There is about 25,000 MW of captive capacity which the industry has created to meet its own demand. A part of that capacity can come to the Grid. Therefore, we are doing multifarious activities. Madam, I would like to take the House into confidence and point out that there is nothing like surplus power available with the Central Government. Power is a commodity which ohce generated has to be consumed instantly. Therefore, we do not have any excess capacity available which you can keep on giving to one State or the other. If we want to give additional power to Karnataka, we will have necessarily have to make a cut out in the quota of other States. And all the States are facing this problem. Therefore, we have called a meeting of the States. We really need to take a national view on this. It is a very serious matter. We are confident that we will tackle it with the cooperation of all concerned.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yesterday there was a Grid failure *....(Interruptions)...* Only One Member can speak at a time. *...(Interruptions)...*

SHRI PRAFUL PATEL: Madam, the Power Minister has just now said that virtually every State is facing shortage of power. We all know that. We have been reading it in the newspapers. You have just mentioned about the power crisis of yesterday. Now, we have also tried in the last few years, in the last 10 or 11 years after liberalisation alternative fuels and the new projects to be based on that. Our own experience in the last ten years has been very dismal. In fact, barring a few projects here and there, virtually, *all* the projects have been non-starters. As a result, we have seen that the only fallback is on thermal generation. But in thermal generation, we have a limitation because most of the coal is concentrated in a few States of the Country. The question basically, was on Delhi getting

power from Korba-Chhattisgarh.The fact of the matter is, now that most of yogr future power generation in a large way to meet this power crisis- as you said it is a national problem-can only be done if you concentrate on generation of power in those States where you have adequate coal. You just said that you are asking the States to reduce the sales-tax oh naphtha or give other kinds of relief. These are all very, very difficult things which we have not been able to addrea for years and years together. We have been talking about it, But we have not really been able to address it.

उपसभापति : क्या अपना क्वेश्चन छोटा करेंगे?

श्री प्राफुल्ल पटेल : मैडम, बहुत दिनों के बाद मैंने प्रश्न पूछा है इसलिए my point is this. You talked of a power trading corporation. But ail these things in power sector reforms did not come along with the total package, and, you see the way it was really mooted. Do we hlave a policy where you can produce power in those States where there is adquate coal, and transport it all over the country? Yes; you have the NTPC and you have a power grid. But our success in that also has not been adequate. Therefore, do you have any comprehensive policy to transmit the power which you generate in these coal-surplus States, to all the States of the country?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a policy matter.

SHRI SURESH PRABHU: Madam, it is a very relevant point. In the past we did not have a policy of generating power at stations where coal was located. Now, we have changed that pdlicy. We are calling it pithead position policy. Where the coal is located we should try to generate the power there itself rather than transporting coal to places thousands of kilometres away and then generating power. Therefore, this Is a new policy which has already been started. In fact, the proposal for 1000 MW power plant to be located in Chhattisgarh-Korba and about which a question has been put by the hon. Member, is an indicator of that. There is already a talk going on between Gujarat and Chhattisgarh to set up a similar station Which means power will be generated in Chhattisgarh and it will be transmitted to Gujarat. Madam, in fact, a study has been made which shows that there could be at least a saving of 60 paise per unit when power is generated at a pithead station rather than transporting the coal to tariff places. lt is cheaper to transmit the power which is generated at the pithead stations. In fact, the saving in this case would be something

like Rs. 500 crores per annum. Therefore, it is a policy decision that we have taken. To implement this policy further, we not onjy need generating stations but we also neecl evacuating capacity. So, my Ministry has already planned setting up of a national grid; and the Cabinet is going to consider this proposal very shortly.Therefore.a national grid will be created with an Investment of Rs. 80,000 crores. This nationai grid will then be able to transmit power from one place to another. This is the first true national grid in our country. It is the biggest in the world that will come into play within the next ten years.

श्री परमेंश्वर कुमार अग्रवाला : धन्यवाद उपसभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस देश में थर्मल पावर जनरेशन की कितनी कैपेसिटी है और कितनी थर्मल पावर जनरेट हो रही है? जहां तक मैं जानता हूं यदि प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाया जाए तो एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया जा सकता है। प्लांट लोड फैक्टर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं मिल रहा है। 44-50 परसेंट की ऐश वाला कोयला मिल रहा है। मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाई पोल्युटिड एरियाज के पावर प्लान्ट्स में 34 परसेंट से ज्यादा राख का कोयला यूज नहीं कर सकते हैं। इस विषय में मंत्री जी क्या नीति है, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री सुरेश प्रभु : उपसभापति महोदया, हमारे देश में ऑल इंडिया बेसिस पर जो प्लांट लोड फैक्टर है, वह ६९.९ परसेंट हैं। लेकिन पूर्वी भारत में हमारा प्लांट लोड फैक्टर कम है। इसकी दो वजह है। एक तो यह कि पूर्वी भारत में सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रिब्यूशान नेटवर्क ठीक न होने की वजह से और दूसरा सपरेस्ड डिमांड होने की वजह से वहां जितना प्लांट लोड फैक्टर होने की जरूरत है , उतना नहीं है। जैसे इस राज्य मे प्लांट लोड फैक्टर पंद्रह प्रतिशत है। नेशनल स्तर पर कुछ पावर स्टेशन, जैसे एन.टी.पी.सी. के पावर स्टेशन हैं उनका नाइनटी परसेंट से ज्यादा पावर जनरेशन होता है। ओन एन एवरेज नेशनल लेवल पर ६९.९ परसेंट की ऐवरेज है। इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कोयले की क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेन्ट इश्यू हैं। इसके लिए हम कोशिश कर हरे हैं कि कोयले की क्वालिटी कैसे सुधारी जाए। कोयले में यदि पत्थर ज्यादा होगा और कोयला कम होगा तो इसका असर पावर जनरेशान पर पड़ेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Power is a very important subject. What we have been discussing here is a very limited issue pertaining to setting up of captive power plant- for power supply to DelhMn Chhattisgarh.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We understand the importance of -power. Because of this, your vocal power has broken up.

THE DEPUTY CHAIRMAN: My battery has weakened.

श्री सुरेश पचौरी : मैडम, देश में पावर क्राइसेस हैं और सरकार में पावर ट्रांसफर हो रही है।

एक माननीय सदस्य : हो नहीं रही है, हो गई हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would be very happy if we can have a fulfledged discussion on this subject

श्री दत्ता मेघे : मैडम, एक भी क्वेश्चन पूछने का अवसर नही मिला है।

उपसभापति : अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरूआत ही हुई है।

श्री रमा शंकर कौशिक : आपने आप सभी को उदारतापूर्वक सवाल से हटकर प्रश्न पूछने का मौका दिया है, हमें भी सवाल पूछने का को मौका दें।

उपसभापति : मंत्री जी न नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। वे तो हर जवाब के लिए तैयार है।

श्री बालकवि बैरागी : उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से सीधे ही उस मुद्दे पर सवाल करना चाहता हूं जिस मुद्दे पर हमारे विद्वान भाई , संसद सदस्य श्री अखिलेश जी ने आपके समाने यह प्रश्न किया है। महोदया, यह संकल्पना, यह प्रस्ताव बहुत पुराना है। यह संकल्पना तब की है जब मध्य प्रदेश बड़ा था और छत्तीसगढ़ नहीं बना था, यह प्रस्ताव उस वक्त का है। उस वक्त विशाल मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए तत्तकलीन सरकार ने जो पहल की थी या जो कुछ सुविधाएं पूरे मध्य प्रदेश के लिए इस विद्युत की संकल्पना में शमिल की थी और अब जो ताजा प्रस्ताव आप काम में लाने वाले हैं क्या उसमें उसका समावेश होगा या वे हिस्से निकाल दिए जांएगे? इस बारे में कोई नीति या सकंल्पना का प्रस्ताव आपके सामने स्पष्ट हो तो आप कृपा करके इस पर स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेश प्रभु : मैंडम, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह केन्द्र सरकार का प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लगाना चाहती हैं। वहां से पावर इवेक्युऐट करके दिल्ली के लिए आ जाएगी ....(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी : मेरा आपसे आग्रह हैं कि ....(व्यवधान)...

उपसभापति : आपका सवाल हो गया है, और भी दूसरे लोग हैं।

श्री बालकवि बैरागी : यह जो संकल्पना है, यह पुराने मध्य प्रदेश के वक्त में की गई संकल्पना है, जब दिल्ली से बातचीत हो रही थी। आज जो बातचीत होने वाली है या जो आकार

लेने वाली है, उसमें क्या कोई ऐसी पहल करेंगे कि शेष मध्य प्रदेश, जो बड़ा है उसके हित भी सुरिक्षत रह सके और दिल्ली वालों से मिलकर जो बात करें उसमें उसका समावेश हो सके।

श्री सुरेश प्रभु : छत्तीसगढ़ में सिर्फ पावर जनरेट की जाएगी और पूरी की पूरी पावर दिल्ली के लिए लाई जाएगी। इसके लिए वहां के कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अच्छे संबंधों को ध्यान में रखते हूए अगर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को इसमें से कुछ देना चाहेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री द्त्ता मेघे : मैं मत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे महाराष्ट्र से आते हैं । ये तो अभी नया बनाने का प्रोपोजल है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एनरॉन का प्रोजेक्ट है जिन्होंने करोड़ो रूपएं खर्च किए । फारन से बहुत पैंसे खर्च करके बिजली बनी। लेकिन वह जो प्रोजेक्ट है, जो बिजली बनी हुई है, वह लोगों को नहीं मिलती है। उसका नतीजा है कि कल गुजरात, महाराष्ट्र आदि चार स्टेट्स अंधेरे में रही । एनरान का जो प्रोजेक्ट है उसमें केंन्द्र सरकार बीच में आकर यह जो बिजली निर्मित हुई है, यह पूरे देश में और महाराष्ट्र में देने की क्या कोई कोशिश कर रही है?

उपसभापति : मैं तो खुद महाराष्ट्र से आती हूं। वह सवाल इससे ताल्लुक नहीं रखता है। But if he wants to answer, it is up to him.

श्री दत्ता मेघे : बिजली का सवाल है। जो बिजली करोड़ों रूपए खर्च करने पर पैदा हुई है वह इस्तेमाल नहीं हो रही है।

श्री सुरेश प्रभु : जैसा हमारे सम्माननीय सदस्य जानते हैं कि महाराष्ट्र में आज कम से कम 2500 मेगावाट की लोड शेडिंग महाराष्ट्र सरकार को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां बिजली अवेलेबुल नहीं है। महाराष्ट्र 2100 मेगावाट का बिजली का प्रोजेक्ट डाभोल पावर कंपनी का प्रोजेक्ट है और वह अवेलेबुल है। इसलिए हमारी महाराष्ट्र सरकार से हमेशा प्रार्थना रही है कि जिस कंपनी के साथ आप द्वारा एग्रीमेंट करने के नाते जो प्रोजेक्ट वहां आया और उससे जो बिजली का निर्माण होने वाला है, वह बिजली लेने के लिए यदि कोशिश करें, लेने के लिए तैयार हों तो उसमें दाम घटाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा सकते हैं। आज आईडीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार को एक प्रोपोजल दिया है कि 2.50 रूपए में आप, जो बिजली निर्मित हुई है, वह ले लीजिए। इसलिए कि आज एनरॉन प्रोजेक्ट नहीं है। एनरान तो आज अंडर लिक्विडेशन हैं। इसलिए आज डाभोल पावर कंपनी जिसमें महाराष्ट्र सरकार के 35 परसेंट शेयर्स हैं। इसलिए वह बिजली लेंगे तो दो मिनट में सवाल हल हो सकता है।

उपसभापति : NOW, मनोहर, कान्त ध्यानी। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उसी से संबंधित हो तो कृपया सवाल पूछें नहीं तो पूरे देश में बिजली की कमी के बारे में अगर करना है तो We can

have a full-fledged discussion.

श्री संजय निरूपम : मैंडम, छिटपुट सवाल आ रहे है, छिटपुट जबाव हो रहे हैं। बात नहीं बन रही हैं ....(व्यवधान)...

उपसभापति : बेचारें जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहिए। छिटपुट जवाब नहीं दे रहें हैं, पूरा जवाब दे रहें हैं।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मूल प्रश्नकर्ता ने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल का उल्लेख करते हुए बिजली की कमी का उल्लेख किया था। महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और केंन्द्र सरकार का सयुंक्त उद्यम टिहरी परियोजना है जो 2500 मेगावाट की है और इसको दिसम्बर 2002 में पूरा होना है। इसका कार्य किस तरह से चल रहा है? इससे उत्तर प्रदेश को भारी लाभ होना है। जो उसका जल घटक है वह पूरा का पूरी उत्तर प्रदेश का है और जो विद्युत घटक है उसमें से रायल्टी देकर जो 25 परसेंट है वह उत्तर प्रदेश का है और 75 प्रतिशत केंद्र का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो योजना है उसके कार्य की प्रगति क्या है, मुख्य बांध की प्रगति क्या है, पावर हाउस की प्रगति क्या है और पंप हाउस की प्रगति क्या है?

श्री सुरेश प्रभु : उसके लिए तो डिटेल्स पंपप हाउस आदि के कितने क्याहैं, चाहें तो सम्माननीय सदस्य को लिखित रूप में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। वैसे हमारे सम्माननीय सदस्य, हमारी कंसलटेटिव कमेटी के भी सम्मानीय सदस्य हैं। कल ही मीटिंग है, उसमें भी मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Q. NO. 242 Shri R.S. Gavai.

SHRI R.S. GAVAI: Madam, I do not want to put my question because I do not recognize... *(Interruptions)*

*242.—*withdrawn*

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: How can you say like that? You do not recognise. This is very bad. ...*(Interruptions)*... You are creating a new precedence. ...*(Interruptions)*... Madam, if the hon. Member does not want to put the question, please allow the supplementaries. *(Interruption^)*

उपसभापति : बैठिए... (व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. *(lnterruptions)P\ease* sit down. *(Interruptions* बैठिए ।........(व्यवधान)I am not allowing anybody.

∗Not recorded.

(Interruptions) Nothing will go on record. *(Interruptions)* Nothing will go on record. *(Interruptions)* Please $lt down. *(Interruptions)* Nothing will go on record. *(Interruptions)* Please sit down- *(Interruptions)* Please keep quiet. *(Interruptions)* Mr. Jibon Roy... *(Interruptions)*

श्री जीवन राय : *

श्री संजय निरूपम : *

उपसभापति : आप लोग बैठिए .... (व्यवधान) आप बैठिए।........ (व्यवधान) आप चुप रहिए। .... (व्यवधान) Please sit down. *(Interruptions)* No; no. *(Interruptions)*.. point is, if Members do not want to put questions, they may not put tpem. *(Interruptions)* If you don't put questions, then, we wilj move on to the next question. It is your loss; I have no problem. *(Interruptions).* Question tyo. 243.

श्री एस0 एस0 अहलुवालिया : महोदया, मेरा प्वायंट् आफ् आदर्डर है। ... (व्यवधान)

उपसभापति : अहलुवालिया जी, आपका क्या प्वायंट् आफ् आर्डर है।...(व्यवधान)...

एक मिनट बैठिए, आडवाणी जी कुछ कहना चाहते हैं।

उप प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : उपसभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर चर्चा की आए कि इसका क्या हल हो सकता है, क्योंकि यह स्थिति, यह गतिरोध इस प्रकार से चलता रहे, काफी समय से चला है। आपने अपना विरोध, अपनी नाराजगी भी प्रकट की है। मेरा आपके माध्यम से पूरे विपक्ष से और आपसे भी अनुरोध होगा कि आप विपक्ष के प्रमुख लोगों को और सरकार के प्रमुख लोंगों को बुला करके और इसकी चर्चा करके, इस गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश करें।

उपसभापति : ठीक है, बस हो गया। ......(व्यवधान)NOW, it is over. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)The*
Leader of the Opposition wants to say something.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH):- M$dam, thp hon. Deputy Prime Minister has made a suggestion. We, on this side of the House, want to see utmost normalcy in the functioning of this House.There have been circumstances which led our party to take a particular decision. But, I do agree that we should sit together to find a solution to this problem. The leaders of all political parties can sit together in your Chamber and find a way out. *(Interruptions).*

---

* Not recorded.

श्री नीलोत्पल बसु : सवाल न पूछने का हमार अधिकार है।.........(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; no, it (8 over. *(Interruptions)* Question No. 243. *(Interruptions)* We cannot have a descussion during Question Hour. *(Interruptions)* No; no discussion during Question Hour. *(Interruptions)* I am not permitting anybody. Question No. 243. *(Interruptions)* You must sit down. *(Interruptions)* You must sit down. *(Interruptions)*

श्री नीलोत्पल बसु : *

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. *(Interruptions)* No; no. *(Interruptions)* We cannot have a discussion during Question Hour. *(Interruptions)* Question No. 243. *(Interruptions)*
I have not allowed you to speak.... *(Interruptions)*.... Plase take your seats. ...*(Interruptions)*... I am not listening to you. ..*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ... *(Interruptions)*...Please sit down. ..*(Interruptions)*...^, I am not listening to you. ..*(Interruptions)...Nothing* is going on record. ...*(Interruptions)*... Question No. 243. ..*(lnterruptions)...P\ease* sit down. ..*(Interruptions)*... You must respect the Chair. ...*(Interruptions)*... Please sit down, don't disrupt the Question Hour. ..*(Interruptions)*... Please sit down. ..*(Interruptions)*... Please take your seats. ..*(Interruptions).you* can discuss this matter in my Chamber, but not here. ..*(Interruptions)*... As suggested by the Leader of the Opposition, I am going to discuss this matter. ..*(Interruptions)*... I have not allowed you to speak. ..*(Interruptions)...He* is the Leader of the Opposition. ..*(Interruptions)...]* cannot speak, as much as you can, because of some problem in my throat. ..*(Interruptions)*... Please sit down. ..*(Interruptions)*...Listen to me. ..*(Interruptions)*... बैठिए, एक मिनट...(व्यवधान), .. आडवाणी जी ने जो कहा और उस के ऊपर लीडर आफै द अपोजीशन ने जो रिएक्ट किया है, उसे देखते हुए ।I will call a meeting of the leaders of various parties. ..*(Interruptions)*... Please sit down. ..*(lnterruptions)...You* must respect the Chair. ..*(Interruptions)...]* will not allow anything else during the Question Hour. ..*(Interruptions)*...Whatever you want to discuss, you can discuss it in my *chamber. ..(Interruptions)...]* have accepted the proposition made by Shri L.K. Advani, the Deputy Prime Minister and Dr. manmohan Singh, the hon. Leader of the Opposition. We will discuss this matter. .*(Interruptions)...]* have not allowed you. ..*(Interruptions)*... Question No.

* Not recorded.

243. ..*(lnterruptions)*...I am not allowing you. ..*(Interruptions)*...It is not a Question. ..*(Interruptions)..Mr.* Basu, I don't want you to disrespect the Chair, because you are also in the Panel of Vice-Chairmen. ..*(lnterruptions)...No,* you cannot force me. ..*(Interruptions)*...You are free to do whatever you like. ..*(Interruptions)*..I will not allow anything else during the Question Hour. ..(Interruptions)... Question. No. 243. .*(Interruptions)*... बैठिए, आप को तो कुछ-न-कुछ बोलने की आदत हो गयी है। ...(व्यवधान)... Let them walk out. ..*(Interruptions)*...

At this stage, some hon. Members left the Chamber

उपसभापति : खामोशी से बाहर जाइए। ...(व्यवधान)... हां, शर्मा जी सवाल पूछिए।

Terrorist Activities on the Borders of Jammu end Kashmir and Himachal Pradesh

*243. SHRI ANIL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of violent incidents by the terrorists on the borders of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and some areas of punjab have increased during the last six months;

(b) if" so, the total number of violent incidents occurred in these States during the above period;

(c) the number of security personnel, terrorists and citizens killed in these incidents; and

(d) the steps Government propose to take to prevent such incidents in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHENNAMANENIVIDYA SAGAR RAO):.(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The total number of violent incidents by terrorists and the number of security personnel, terrorists and civilians killed in the States of Jammu and Kashmir, Punjab and Himachal Pradesh during the period from 1 st January 2002 to 30th June 2002 and the corresponding period last year are as follows: